

50/10
 कृष्णगण उपस्थिति / प्रती का प्रती
 10 स्थिति लिखा जाता है। निम्न
 प्रकाश से टिप्पणी लिखा जाता है इत्यादि
 प्रकाश लिखा जाता है। प्रकाश का
 शुभारंभ प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश
 प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश

कृष्णगण उपस्थिति / प्रती का प्रती
 पर राज कार्य से व्यक्त है। आत्म
 प्रकाश दिनांक ... को ...
 प्रकाश ही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, अलवर

मासीन अधिकारी - पुष्कर राज शर्मा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

3/12

18.04.2012

30.10.2012

उनवान

सुभाष पुत्र श्री गोरेलाल जाति जाट
निवासी ग्राम कोटकासिम।

:- प्राथी / वादी

बनाम

दलीपसिंह पुत्र श्री गोरेलाल।
विक्रमसिंह पुत्र श्री गोरेलाल जाति जाटान
निवासी ग्राम कोटकासिम।
राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम
जरिये शाखा प्रबंधक कोटकासिम।
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (लैण्ड होल्डर)
हसीलदार कोटकासिम।

:- अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

परिस्थित अधिवक्ता

श्री नरहरि व्यास - प्रार्थी

श्री विकास यादव - अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या
व 2 की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। अप्रार्थीगण आये दिन
प्रार्थी के शामलाती हिस्से के कब्जे काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है।
दिनांक 16.04.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ऐलानियां तौर पर धमकी दी कि वे प्राथी की
आराजी को बिना बंटाये ही दीगर लोगो को बेचान करेगे और प्रार्थी को उसके हिस्से से
जबरन बेदखल करेगे व कब्जा करेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इन इरादो मे कामयाब हो
गए तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। अजहद की

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

नि होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चन्द्रोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाइड आयद व साबित होता है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थी है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चन्द्रोजा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 137/1-03, 143/3-03, 902/1-04, 2323/0-05 का कुल कित्ता 4 कुल रकबा 5-15 बीघा वाके ग्राग कोटकासिम तहसील कोटकासिम लवर को कही दीगर जगह रहन गय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी के शामलाती हिस्से के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे मौका व जस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

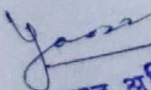
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने झूठे तथ्य दर्ज कर वादपत्र, शपथपत्र पेश किये हैं। जिनसे प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाइड आयद व साबित नहीं होता है। आराजीयात शामलात की नहीं है। प्रार्थी के पर आराजी हक हिस्से अनुसार बांट रखी है व बाहमी बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। परंतु बाहमी बंटवारा को अमलीजामा ना पहनाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड मे शामलात मे दर्ज है।

प्रार्थी के हिस्से मे 1-18 बीघा आराजी आती है। जो उसने खसरा नम्बर 137/1-03, 902/1-04 बीघा मे से प्राप्त कर रखी है व इसी प्रकार शेष रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आपस मे बांट रखा है। बंटवारे के अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 2 ने आराजी खसरा नम्बर 143/3-03 बीघा मे अपनी लागत से सबमर्सिबल बोरिंग करवाया व विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कोटकासिम कार्यालय मे दिनांक 25.03.2008 को पत्रावली जमा करवाई थी व दिनांक 29.07.2011 को डिमाण्ड नोटिस भी जमा करा दिया गया था व विद्युत कनेक्शन हेतु समस्त सामान भी अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी मे डाल रखा है, परंतु प्रार्थी द्वारा बेजा रूप से तंग व परेशान करने की नीयत से उक्त वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गयी जिस कारण विद्युत कनेक्शन अधूरा रह गया व अप्रार्थी संख्या 2 को सिचाई हेतु भारी नुकसान का सामना करना पड रहा है। दिनांक 16.04.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने झूठी व अनघडंत दर्ज की है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी भी सूरत मे हुक्मईम्तनाइ चन्द्रोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि विवादित आराजी शामलाती है। मौके पर कोई बंटवारा नहीं है। प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण के साथ शामलात मे काश्त करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (लवर) राब.

प्राथी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। सुविधा का संतुलन प्राथी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्राथी के पक्ष में है। अतः विभाजन किये जाने तक रिकॉर्ड व के की यथास्थिति रखी जावे।


अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि मोक़े पर आपसी विभाजन हो रखा। अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि में नलकूप बनवाया है एवं विद्युत सम्बंध लेना चाहते हैं। विद्युत सम्बंध लेने हेतु प्राथी ने इस दावे से पूर्व ही अपनी लिखित सहमति दी है। प्राथी अपनी सहमति के कारण पाबंद है एवं अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध लेने से ही रोक सकता। प्राथी शुद्धहस्त से न्यायालय में नहीं आये हैं। अप्रार्थीगण ने पूर्व में ही अपना हिस्सा बैंक में रहन रखा हुआ है परंतु अब अप्रार्थीगण को पाबंद कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सहिस्सेदार है जिन्हें पाबंद कराने का प्राथी को कोई अधिकार नहीं है। प्राथी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन नहीं है। अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध नहीं मिलने के कारण क्षति हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत प्रकरण में जमाबंदी सम्वत् 2067-2070 से स्पष्ट है कि पक्षकारान सखातेदार है। प्राथी द्वारा अपना हिस्सा रहन रखा हुआ है मैं अप्रार्थीगण के इस तर्क से सहमत हूँ कि सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना उचित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थना का उद्देश्य अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध लेने से रोकना है। विद्युत सम्बंध के अभाव में काश्त कार्य किया जाना व भूमि से सही उपज लिया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थीगण को क्षति होने में पूरी सम्भावना है। इसलिए प्राथी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु साबित नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 9 नियम 1 व 2 तथा सपटित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बलवर) राज.